

केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राँची

राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधान ।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3(3) के अनुसार निम्नलिखित कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी में जारी किए जाएं -
(1) संकल्प (2) सामान्य आदेश (3) नियम (4) प्रेस विज्ञापि/विज्ञापन (5) सूचना (6) अधिसूचना (7) संविदा (8) करार (9) अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस) (10) अनुज्ञापत्र (परमिट) (11) निविदा (12) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (13) मंगद के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन ।

राजभाषा नियम-1976 का नियम-5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं ।

राजभाषा नियम-11 के अनुसार निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार करवाया जाए -
(1) नेम प्लेट (2) रबर की मोहर एवं सील (3) फाइल एवं रजिस्टर (4) फार्म प्रपत्र/मानक मसौदे (5) बैनर पोस्टर (6) चार्ट एवं ग्राफ (7) मैप एवं चैज (8) वाहनों पर कार्यालय का नाम (9) साइनबोर्ड (त्रिभाषी)।

हिन्दी पत्राचार का वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2015-16)

क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
1) 'क' क्षेत्र में 'क' व 'ख' क्षेत्र के साथ-100%	1) 'ख' क्षेत्र में 'क' क्षेत्र के साथ 100%	1) 'ग' क्षेत्र में 'क' क्षेत्र के साथ 55%
2) 'क' क्षेत्र में 'ख' क्षेत्र के साथ-100%	2) 'ख' क्षेत्र में 'ख' क्षेत्र के साथ 90%	2) 'ग' क्षेत्र में 'ख' क्षेत्र के साथ 55%
3) 'क' क्षेत्र में 'ग' क्षेत्र के साथ - 65%	3) 'ख' क्षेत्र में 'ग' क्षेत्र के साथ - 55%	3) 'ग' क्षेत्र में 'क' व 'ख' क्षेत्र के साथ संघ राज्य क्षेत्र के प्राशासनिक व साथ 55%
	4) 'ख' क्षेत्र में 'क' व 'ख' क्षेत्र के साथ/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति के साथ - 100%	

राजभाषा कार्यान्वयन में सुविधा की दृष्टि से पूरे देश को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है -

क क्षेत्र :-

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।

ख क्षेत्र :-

महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दमन एवं दीव तथा दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।

ग क्षेत्र :-

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, मिजोरम, पुद्दुचेरी, गोवा, जम्मू व कश्मीर ।

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत कार्य
27/11/15